राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शनिवार, 13 जून 2026

वर्ष 14, अंक 64, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल के साथ सरचार्ज के प्रस्ताव पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा नाराज..03

वैभव सूर्यवंशी का तूफान नहीं आया काम, अफगानिस्तान ने भारत को दी शिकस्त..04

कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता की टीएमसी को राहत नहीं, ऋतब्रत बनर्जी बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष

● स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

● कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति पर ममता बनर्जी की टीएमसी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिससे ऋतब्रत रुखवकबने रहेंगे

● कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले पर रोक नहीं लगाई और अगली सुनवाई 16 जून को होगी. हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या स्पीकर किसी राजनीतिक दल की सहमति के बिना नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दे सकते हैं?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति मामले में फिलहाल ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने विधानसभा स्पीकर के नेता प्रतिपक्ष संबंधी फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई. ऋतब्रत बनर्जी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होगी।

हालांकि विधानसभा में नेता विपक्ष चुने जाने को लेकर सुनवाई के दौरान आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर किसी राजनीतिक दल की सहमति के बिना नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दे सकते हैं?

टीएमसी द्वारा बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में दी गई मान्यता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह जानना चाहा कि क्या स्पीकर किसी विधायक को उसकी मूल पार्टी की इच्छा के विपरीत नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे सकते हैं या फिर इस मामले में संबंधित राजनीतिक दल की राय और आधिकारिक निर्णय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्पीकर ने ऋतब्रत को LoP की दी है मान्यता

बता दें कि ऋतब्रत बनर्जी ने टीएमसी के 59 बागी विधायकों के साथ अलग गुट बना लिया है और विधानसभा अध्यक्ष ने इस गुट को मान्यता देते हुए ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया है. इसी के खिलाफ ममता बनर्जी की टीएमसी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने स्पीकर के एक्शन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की. उन्होंने तर्क दिया कि ऋतब्रत बनर्जी को मान्यता देना, एंटी-डिफेक्शन फ्रेमवर्क के तहत राजनीतिक पार्टियों और लेजिस्लेटिव पार्टियों को कंट्रोल करने वाले संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ था.

कल्याण बंद्योपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि चुने हुए विधायकों की एक मीटिंग 6 मई को हुई थी, जहां सोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया था. उन्होंने कहा कि सपोर्ट करने वाले विधायकों के हस्ताक्षर इकट्ठा किए गए और सोभनदेब चट्टोपाध्याय के पक्ष में जमा किए गए, और स्पीकर को पार्टी के फैसले के बारे में कई बार बताया गया था।

स्पीकर के फैसले पर कल्याण ने जताई आपत्ति

उन्होंने कहा किइसके बावजूद, स्पीकर ने कथित तौर पर 59 विधायकों के समर्थन वाले एक विरोधी ग्रुप को मान्यता दे दी. राजनीतिक पार्टी मर्जर और महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए, कल्याण बंद्योपाध्याय ने तर्क दिया कि संविधान का दसवां शेड्यूल सिर्फ लेजिस्लेटिव पार्टी के बजाय राजनीतिक पार्टी को प्राथमिकता देता है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद टीएमसी में टूट जारी है. विधायक दल के टूट के बाद अब संसदीय दल भी टूट के कगार पर है और टीएमसी के तीन राज्यसभा के सांसद भी इस्तीफा दे चुके हैं।

सरकारी पक्ष की दलीलें

दूसरी तरफ, अंतरिम राहत का विरोध करते हुए राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) बिलवादल भट्टाचार्य ने इस याचिका को अधूरा बताया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका में स्पीकर के फैसले को रद्द करने की कोई स्पष्ट मांग नहीं की गई है. उन्होंने कोर्ट से संबंधित दस्तावेज और असेंबली रिकॉर्ड पेश करने के लिए थोड़ा समय मांगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी रिकॉर्ड के साथ एक हलफनामा दायर करेगी और इस याचिका की वैधता पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी।

आगे क्या होगा?

हाई कोर्ट अब इस मामले से जुड़े सभी आधिकारिक दस्तावेजों और राज्य सरकार के हलफनामे की समीक्षा के बाद ही कोई अगला आदेश जारी करेगा. इस फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका असर दलबदल विरोधी कानून की भविष्य की व्याख्याओं पर भी पड़ सकता है।

लद्दाख में जाम का 'रेड अलर्ट'! नुब्रा-पांगोंग रोड पर वाहनों की लंबी कतार

● लद्दाख के नुब्रा-पांगोंग मार्ग पर लगे भारी ट्रैफिक जाम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अनियंत्रित पर्यटन और पर्यावरणीय दबाव को लेकर बहस छिड़ गई है.

● वीडियो में सैकड़ों वाहन संकरी पहाड़ी सड़क पर फंसे दिखाई दे रहे हैं

लद्दाख के खूबसूरत नुब्रा-पांगोंग मार्ग पर लगे लंबे ट्रैफिक जाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सैकड़ों वाहन संकरी पहाड़ी सड़क पर कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं. इस दृश्य ने एक बार फिर लद्दाख में बढ़ते पर्यटन और उसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में वाहनों और पर्यटकों का दबाव सही है. कई यूजर्स ने चिंता जताई है कि अनियंत्रित पर्यटन से यहां की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है.

वायरल वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में वाहनों की संख्या सीमित की जानी चाहिए और पर्यटकों को सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, 'धीरे-धीरे यह मनाली बनता जा रहा है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इसको भी गुरुग्राम बना दिया.' इस तरह की प्रतिक्रियाएं यह दिखाती हैं कि लोग लद्दाख में बढ़ती भीड़ को लेकर चिंतित हैं. इसे क्षेत्र की पहचान के लिए खतरा मान रहे हैं।

पर्यटन बढ़ने से बढ़ा दबाव

नुब्रा-पांगोंग मार्ग लद्दाख के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है. यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. पिछले कुछ सालों में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे सड़कों पर दबाव बढ़ गया है. विशेषकर पर्यटन सीजन के दौरान इस मार्ग पर भारी भीड़ देखने को मिलती है. सड़कें संकरी होने के कारण वाहनों को आगे निकलने का मौका नहीं मिलता और लंबे जाम की स्थिति बन जाती है. इससे यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है।

पर्यावरण और वाहनों पर भी असर

विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहने से सिर्फ यात्रियों को परेशानी नहीं होती, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है. वाहनों के लंबे समय तक चालू रहने से ईंधन की खपत बढ़ती है और प्रदूषण भी अधिक होता है. इसके अलावा लगातार रुकने और चलने की स्थिति से इंजन, ब्रेक, क्लच और अन्य मशीनरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. बाइक चालकों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक सफर करना शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है। वायरल वीडियो के बाद एक बार फिर लद्दाख में टिकाऊ पर्यटन (सस्टेनेबल टूरिज्म) की जरूरत पर चर्चा शुरू हो गई है. पर्यावरण विशेषज्ञ और संरक्षणवादी मानते हैं कि क्षेत्र की वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए वाहन प्रवेश को नियंत्रित किया जाना चाहिए. साथ ही सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन नीतियां लागू करने की मांग भी उठ रही है।

यात्रियों को दी गई सलाह

प्रशासन और यात्रा विशेषज्ञों ने पर्यटकों को सलाह दी है कि वे भीड़भाड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी यात्रा शुरू करें और पहाड़ी मार्गों पर निकलने से पहले अपने वाहनों की पूरी जांच कर लें. लद्दाख का यह वायरल ट्रैफिक जाम एक बार फिर यह याद दिलाता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।

संक्षिप्त ख़बरें

समुद्र में टला बड़ा धमाका! भारतीय नौसेना ने तेल टैंकर से निकाला जिंदा मिसाइल वारहेड

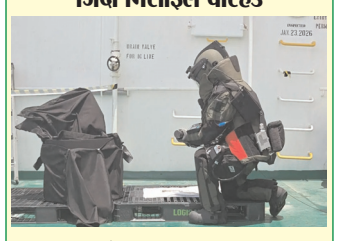

भारतीय नौसेना ने एक बेहद जोखिम भरे समुद्री ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए एक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वारहेड को सुरक्षित तरीके से निकालकर निष्क्रिय किया. नौसेना की इस कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ 26 मई 2026 को यूएई के फुजैराह से कोच्चि आ रहा था. इसी दौरान ओमान तट के पास जहाज के ढांचे में विस्फोट की सूचना मिली। जांच के दौरान पता चला कि जहाज में एक बिना फटा मिसाइल प्रोजेक्टाइल मौजूद है. इसके बाद सूचना भारतीय नौसेना को दी गई. उसके बाद नौसेना ने इस मामले में त्वरित एक्शन लिया।

जहाज के फ्यूल टैंक में मिला मिसाइल वारहेड

भारतीय नौसेना के इन्फॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर इंडियन ओशन रीजन (आईएफसी-आईओआर) को सूचना मिलने के बाद कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड ने तुरंत एक्स्पर्ट ईओडी (विस्फोटक आयुध निपटान)) टीम भेजी। जांच में सामने आया कि मिसाइल का हिस्सा जहाज के बाहरी ढांचे को चीरते हुए कई कम्पार्टमेंट पार कर फ्यूल टैंक के अंदर फंस गया था। फ्यूल स्टोरेज एरिया में जिंदा वारहेड मिलने से बड़ा विस्फोट होने का खतरा था।

बेहद सावधानी से चलाया गया ऑपरेशन

नौसेना की ईओडी टीम ने चरणबद्ध तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले सुरक्षा प्रक्रिया पूरी की गई, फिर आधुनिक तकनीक की मदद से वारहेड के डिटोनेशन सिस्टम की पहचान कर उसे अलग किया गया। इसके बाद मिसाइल वारहेड और उससे जुड़े मलबे को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया. बरामद विस्फोटक सामग्री को आगे की जांच के लिए सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है. भारतीय नौसेना ने कहा कि यह ऑपरेशन उसकी तकनीकी एक्सपर्टीज, समुद्री सुरक्षा क्षमता और आपात स्थितियों में तेज प्रतिक्रिया का उदाहरण है।

दक्षिणांचल के थानों में वीपीओ सिस्टम पर उठे सवाल, अवैध वसूली और प्रभावशाली भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

खजनी, गोरखपुर। दक्षिणांचल क्षेत्र के कई थानों में तैनात वीपीओ (बीट पुलिस अधिकारी) की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ वीपीओ अपने निर्धारित दायित्वों से आगे बढ़कर थाना संचालन और क्षेत्रीय गतिविधियों में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। आरोप है कि ऐसे कर्मियों की पकड़ थानों में इतनी मजबूत हो चुकी है कि कई मामलों में उनकी राय और सिफारिश को विशेष महत्व दिया जाता है।

क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कुछ थानों में वर्षों से जमे वीपीओ स्थानीय दबंगों, भूमाफियाओं, खनन एवं वन माफियाओं से निकट संबंध बनाए हुए हैं। आरोप है कि इन्हीं संपर्कों के माध्यम से अवैध वसूली का नेटवर्क संचालित किया जाता है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में इसको लेकर व्यापक चर्चा बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार, थानों में तैनात कुछ प्रभावशाली वीपीओ थाना प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। थाने के दैनिक खर्च, मेस व्यवस्था तथा अन्य आंतरिक व्यवस्थाओं की जानकारी और समन्वय भी उनके माध्यम से संचालित होने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि उन्हें थाना प्रभारी का करीबी माना जाता है।

स्थानीय पुलिसकर्मियों के बीच भी यह चर्चा रहती है कि मनचाही बीट पर तैनाती अथवा सुविधाजनक ड्यूटी पाने में ऐसे प्रभावशाली कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आरोप यह भी है कि कई बार थाना प्रभारी बदल जाते हैं, लेकिन वर्षों से जमे कुछ कर्मचारी अपनी पकड़ बनाए रखते हैं और स्थानांतरण के बावजूद पुराने क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

क्षेत्रीय नागरिकों का दावा है कि सड़क किनारे लगने वाले अवैध ठेलों, खोमचों, अवैध पार्किंग स्थलों तथा अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से कथित वसूली की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। इसके अलावा खनन, भूमि और वन संपदा से जुड़े मामलों में भी अवैध लेन-देन की चर्चाएं सुनाई देती हैं।

कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट अथवा अन्य विवादों के मामलों में समझौता कराने के लिए दबाव बनाया जाता है और असहमति की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की आशंका दिखाकर पक्षों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। क्षेत्र के नागरिकों का मानना है कि पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि शिकायतों में सच्चाई पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पुलिस व्यवस्था में जनता का विश्वास और मजबूत हो सके।

जिलाधिकारी ने तुलसी सदन का किया निरीक्षण

सौंदर्यीकरण एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश

प्रतापगढ़। जनपद के प्रमुख सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के केंद्र तुलसी सदन का जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा, पार्किंग एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बेल्हा राकेश कुमार को निर्देशित किया कि तुलसी सदन परिसर में नियमित एवं प्रभावी साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि यहां आने वाले नागरिकों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने फायर सेफ्टी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित एवं सुचारु बनाने के निर्देश भी दिए।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर के सौंदर्यीकरण एवं नियमित रखरखाव पर विशेष जोर देते हुए कहा कि तुलसी सदन जनपद की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए इसकी सुंदरता, स्वच्छता एवं सुविधाओं का उच्च स्तर पर संरक्षण किया जाना आवश्यक है। उन्होंने परिसर में आवश्यक मरम्मत कार्यों एवं सुविधाओं के उन्नयन के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।

एक बार फिर हिली असम की धरती, 4.2 तीव्रता के भूकंप से सहमे लोग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

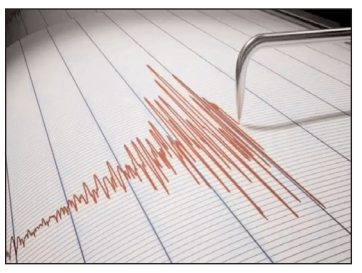

असम के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रात करीब 9:10 बजे आए इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2 रही. कई इलाकों में हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं है. इससे पहले रविवार देर रात भी राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे. भूटान के पास अनुमानित तीव्रता 5.7 का भूकंप आया था. भूकंप का केंद्र असम के कुछ हिस्सों से करीब 252 किमी दूर था. इससे पूर्वोत्तर के कई इलाकों में झटके महसूस किए गए थे।

पूर्वोत्तर भारत में समय-समय पर छोटे और बड़े भूकंप आते रहते हैं. इनकी वजह है इस क्षेत्र की भौगोलिक और भूगर्भीय स्थिति है. वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वोत्तर भारत धरती की उन एक्टिव टेक्टोनिक प्लेटों के संगम के पास है, जहां भूगर्भीय हलचल होती रहती है।

यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है भारतीय प्लेट

दरअसल, भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। करोड़ों सालों से जारी इस टक्कर की वजह से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ. यह प्रक्रिया आज भी जारी है. प्लेटों के बीच का तनाव समय-समय पर अचानक मुक्त होता है, इससे भूकंप आते हैं।

राज्य के नीचे और आसपास कई फॉल्ट लाइन

असम की स्थिति भी इस लिहाज से संवेदनशील है। राज्य के नीचे और आसपास कई सक्रिय फॉल्ट लाइन्स हैं. ये ऐसी दरारें हैं जहां चट्टानें एक-दूसरे के सापेक्ष खिसकती हैं। जब इन क्षेत्रों में दबाव बढ़ता है तो ऊर्जा निकलती है. इससे धरती कांप उठती है. मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में भी यही स्थिति है।

6 दिन बाद भी अंधेरे में हैं आधा दर्जन गांवों की आबादी

● ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही का आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रूद्रपुर, देवरिया। दोआबा के आधा दर्जन गांव के लोग आंधी तूफान के 6 दिन बाद भी बिजली के लिए तरस रहे हैं।भीषण गर्मी में उन्हें कहीं चैन नहीं मिल पा रहा है। ना तो मोबाइल ही चार्ज हो पा रहा है और ना ही आवश्यक कार्य पूरे हो पा रहे हैं। लोगों की रातों की नींद उड़ गई है और दिन का चैन छिन गया है। कुछ गांव में ग्राम प्रधान और ग्राम वासियों की मदद से आंशिक रूप से बिजली बहाल हो सकी है किंतु ज्यादातर गांव में अभी पोल व तार जस के तस पड़े हुए हैं ।जानकारी के अनुसार शुक्रवार को आई चक्रवाती आंधी में पचरूखा उपकेंद्र से संचालित दर्जनों गांव की बिजली बाधित हो गई थी। ग्राम प्रधानों व गांव वालों के सहयोग से कुछ गांवों की बिजली कमोवेश बहाल कर दी गई है। कई गांव में पोल व तार लगाने के नाम पर धन वसूली की खबरें भी आ रही हैं। संविदा कर्मचारी बिजली चालू करने के बदले में गांव वालों से मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं।

6 दिन बीतने के बाद भी भिरवां, नारायणपुर, बहोरा दलपतपुर, पांडे माझा, शीतल माझा आदि गांव की बिजली बहाल नहीं हो सकी है जिसे लेकर लोगों में बिजली निगम व जनप्रतिनिधियों के प्रति रोष व्याप्त है। सबसे ज्यादा परेशान बहोरा दलपतपुर के दर्जनों उपभोक्ता हैं। गांव में केवल पोल पर एलटी तार लगाना है किन्तु विभाग हीला सवाली कर रहा है। गांव वासी अजीत द्विवेदी, कृपानन्द दूबे, राम सिंगार, रामजी, ह्रषिकेश मिश्र,प्रमोद धर द्विवेदी आदि ने कहा कि यदि शीघ्र बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो लोग सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। जेई शिवकुमार ने कहा कि 24 घंटे में गांव की बिजली चालू कर दी जाएगी।

बिहार टेंडर घोटाला: आईएएस संजीव हंस की तलाश तेज, कई बड़ी मछलियां अब भी रडार पर

● बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में विशेष निगरानी इकाई ने एक अधिकारी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है

● रिशु श्री से पूछताछ के आधार पर यह कार्रवाई हुई. पूछताछ के बाद भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कई परतें खुली हैं

● मुमुक्षु चौधरी और तारिणी दास जैसे बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं. वहीं आईएएस संजीव हंस की तलाश जारी है, जो फरार चल रहे हैं।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिहार में सरकारी ठेकों में कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में आज यानी गुरुवार को विशेष निगरानी ने एक अधिकारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस पूरे घोटाले का अहम किरदार है रिशु श्री है, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब रिशु श्री से पूछताछ के आधार पर ही इस घोटाले की परतें खुल रही हैं और इसमें कई बड़ी मछलियां जाल में फंस रही हैं. रिशु श्री प्रकरण में जांच एजेंसियों ने शिकंजा और कस दिया है।

विशेष निगरानी इकाई की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने बिहार की नौकरशाही और ठेकेदारी जगत में खलबली मचा दी है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, इंजीनियर तारिणी दास और इंजीनियर उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार आईएएस संजीव हंस की तलाश तेज कर दी गई है. जांच एजेंसियों का दावा है कि ठेकेदार रिशु श्री के जरिए सरकारी ठेकों में कमीशनखोरी और प्रभाव के दम पर करोड़ों रुपये के खेल को अंजाम दिया गया।

आईएएस संजीव हंस समेत कई अफसरों पर एक्शन

एसवीयू ने अब तक संजीव हंस, तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरी और पंकज कुमार समेत कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. मुमुक्षु चौधरी पर आरोप है कि सीतामढ़ी और सहरसा में नगर आयुक्त रहते हुए उन्होंने कथित रूप से रिशु श्री की कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए कमीशन लेकर ठेके आवंटित किए. 27 मार्च 2025 को ईडी की छापेमारी में उनके ठिकाने से करीब 2 करोड़ रुपया बरामद हुआ था. वर्तमान में वे वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच जारी है।

ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपये नकद बरामद

वहीं संजीव हंस पर जल संसाधन, ऊर्जा और अन्य विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए रिशु श्री की कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है. ईडी, सीबीआई और एसवीयू की अलग-अलग जांचों में उनका नाम सामने आया है. पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास भी जांच के घेरे में हैं. ईडी की छापेमारी में उनके यहां से करोड़ों रुपये नकद बरामद हुआ था।

जांच एजेंसियों को यह भी सुराग मिला है कि रिशु श्री से जुड़ी एक अतिरिक्त कंपनी के माध्यम से कथित तौर पर काले धन को सफेद करने का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था. जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित भ्रष्टाचार तंत्र से किन-किन अधिकारियों, ठेकेदारों और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचा।

जब भारत ने सैन्य विमान निर्माण में रचा नया इतिहास

भारत ने रक्षा और विमानन क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसे आने वाले वर्षों में देश की औद्योगिक और सामरिक प्रगति के महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा और एयरबस की अंतिम संयोजन इकाई में निर्मित पहले सी-295 सैन्य परिवहन विमान ने सफलतापूर्वक अपनी पहली परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। यह केवल एक विमान की उड़ान नहीं थी, बल्कि उस विश्वास, क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता की उड़ान थी, जिसकी कल्पना भारत लंबे समय से करता रहा है। इस उपलब्धि ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, बल्कि वह उन्नत रक्षा प्रणालियों और सैन्य विमानों के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सी-295 कार्यक्रम भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करने वाली सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गिना जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए कुल 56 सी-295 विमानों की खरीद का निर्णय लिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत 16 विमान सीधे स्पेन से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जा रहा है। यही वह पहल है जिसने देश में सैन्य विमान निर्माण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। इन 40 विमानों का निर्माण वडोदरा में स्थापित उत्पादन परिसर में किया जाएगा, जहां भारतीय इंजीनियर, तकनीशियन और विशेषज्ञ वैश्विक स्तर की प्रौद्योगिकी के साथ काम कर रहे हैं।

पहले भारत निर्मित सी-295 विमान की सफल परीक्षण उड़ान ने इस परियोजना की व्यवहारिक सफलता को प्रमाणित कर दिया है। यह उड़ान उत्पादन के बाद होने वाली परीक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण थी। किसी भी सैन्य विमान को सेवा में शामिल करने से पहले उसकी विभिन्न प्रणालियों, उड़ान क्षमता, नियंत्रण व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र और प्रदर्शन का कठोर परीक्षण किया जाता है। पहली सफल उड़ान यह दर्शाती है कि विमान निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार हुआ है और आगे की परीक्षण प्रक्रियाओं के लिए सक्षम है। भारत में निर्मित पहला सी-295 विमान मई 2026 में पूरी तरह तैयार हुआ था। इसके बाद जून 2026 में उड़ान परीक्षणों का दौर प्रारंभ हुआ। इस सफल परीक्षण के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारत में निर्मित पहला विमान इसी वर्ष भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। यह उपलब्धि केवल रक्षा क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय विनिर्माण क्षमता के लिए भी गर्व का विषय है।

सी-295 एक मध्यम श्रेणी का सामरिक परिवहन विमान है, जिसे अनेक प्रकार के सैन्य अभियानों के लिए विकसित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी बहुउद्देश्यीय उपयोगिता है। यह विमान एक बार में 71 सैनिकों या लगभग 50 पैराट्रूपरों को ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसका उपयोग रसद आपूर्ति, चिकित्सा निकासी, आपदा राहत, विशेष सैन्य अभियानों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित तैनाती जैसे कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। भारत जैसे विशाल और विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश के लिए ऐसे विमान का महत्व और भी बढ़ जाता है। हिमालयी क्षेत्रों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों तथा समुद्री सीमाओं तक, भारतीय सशस्त्र बलों को विभिन्न परिस्थितियों में त्वरित परिवहन क्षमता की आवश्यकता होती है। सी-295 को इसी उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। यह छोटी और अपेक्षाकृत कम विकसित हवाई पट्टियों से भी उड़ान भर सकता है और उतर सकता है। इसकी यह क्षमता उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है जहां सामान्य बड़े विमान संचालन नहीं कर सकते।

इस विमान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। यह अस्थायी अथवा अर्धविकसित रनवे पर भी संचालन करने में सक्षम है। पूर्ण अंधकार की स्थिति में भी इसकी संचालन क्षमता इसे आधुनिक सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है। युद्धकालीन परिस्थितियों में ऐसी क्षमताएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं

क्योंकि सैन्य अभियानों में अक्सर सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। सी-295 कार्यक्रम केवल विमान निर्माण तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से भारत में एक व्यापक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित हो रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत हजारों पुर्जों का निर्माण भारत में किया जा रहा है। अनेक भारतीय कंपनियां इस आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनी हैं। इससे देश में उच्च तकनीकी विनिर्माण क्षमता का विकास हो रहा है और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13000 से अधिक पुर्जों का निर्माण भारत में किया जा रहा है तथा दर्जनों भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को उत्पादन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इससे केवल एक विमान नहीं बन रहा, बल्कि एक संपूर्ण औद्योगिक आधार तैयार हो रहा है जो भविष्य में अन्य रक्षा और विमानन परियोजनाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी है। जब किसी उन्नत विमान का निर्माण देश में किया जाता है, तो उससे जुड़े डिजाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण संबंधी अनेक कौशल स्थानीय स्तर पर विकसित होते हैं। इससे भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों को अत्याधुनिक तकनीक के साथ काम करने का अवसर मिलता है। दीर्घकाल में यही अनुभव भारत को अधिक जटिल और उन्नत विमान प्रणालियों के स्वदेशी विकास में सहायता करेगा।

सी-295 कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण से भी जुड़ा हुआ है। वर्तमान में यह विमान पुराने एवरो परिवहन विमानों का स्थान ले रहा है, जो कई दशकों से सेवा में हैं। बदलती सैन्य आवश्यकताओं और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए अधिक सक्षम और आधुनिक परिवहन विमानों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सी-295 इस आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी बेहतर वहन क्षमता, आधुनिक प्रणालियां और बहुउद्देश्यीय उपयोगिता भारतीय वायुसेना की परिचालन दक्षता को बढ़ाएंगी।

वडोदरा में स्थापित उत्पादन केंद्र स्वयं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सुविधा की स्थापना ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जहां आधुनिक सैन्य परिवहन विमानों का निर्माण किया जाता है। यह केंद्र भविष्य में अन्य विमानन परियोजनाओं के लिए भी आधार बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी प्रकार की परियोजनाएं आगे बढ़ती रहीं, तो भारत वैश्विक विमानन आपूर्ति श्रृंखला में और अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल हथियारों का निर्माण नहीं है, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता भी है। जब कोई देश अपनी आवश्यक सैन्य प्रणालियों का निर्माण स्वयं करता है, तो वह बाहरी निर्भरता को कम कर पाता है। संकट या युद्ध की स्थिति में विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कई बार जोखिम पैदा कर सकती है। ऐसे में सी-295 जैसी परियोजनाएं भारत की सामरिक स्वायत्तता को मजबूत करती हैं। इस उपलब्धि का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी से निवेश, रोजगार, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय उद्योगों को नए अवसर मिलते हैं और तकनीकी दक्षता का स्तर ऊंचा होता है। इससे देश की समग्र औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होती है। रक्षा विनिर्माण को अक्सर उच्च तकनीकी उद्योगों के विकास का आधार माना जाता है क्योंकि इसके लिए अत्यंत सटीक और उन्नत उत्पादन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

पहले भारत निर्मित सी-295 की सफल परीक्षण उड़ान इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह निजी क्षेत्र की भागीदारी का एक सशक्त उदाहरण है। लंबे समय तक रक्षा उत्पादन मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों तक सीमित रहा, लेकिन अब निजी उद्योग भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। टाटा और एयरबस की साझेदारी यह दिखाती है कि वैश्विक अनुभव और भारतीय क्षमता का संयोजन किस प्रकार विश्वस्तरीय परिणाम दे सकता है।

आने वाले वर्षों में जब सभी 40 विमान भारत में निर्मित होकर भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे, तब इस परियोजना का वास्तविक प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देगा। इससे न केवल वायुसेना की परिवहन क्षमता मजबूत होगी, बल्कि भारत की औद्योगिक और तकनीकी शक्ति को भी नई पहचान मिलेगी। यह परियोजना भविष्य की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकती है जिनमें अधिक उन्नत सैन्य विमान, मानव रहित प्रणालियां और अन्य एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म देश में विकसित और निर्मित किए जाएं। सी-295 की पहली सफल उड़ान वस्तुतः उस नए भारत का प्रतीक है जो आत्मविश्वास के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यह उपलब्धि केवल एक विमान की सफलता नहीं, बल्कि भारतीय प्रतिभा, औद्योगिक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टि और राष्ट्रीय संकल्प की सफलता है। आने वाले समय में जब यह विमान भारतीय आकाश में वायुसेना के रंगों के साथ उड़ान भरेगा, तब वह केवल सैनिकों और सामग्री का परिवहन नहीं करेगा, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की आकांक्षाओं को भी अपने साथ लेकर चलेगा।

महेन्द्र तिवारी

मोदी की 12 वर्षों की सत्ता और आम आदमी: वादे, बदलाव और ज़मीनी हकीकत

संपादक/लेखकः राजीव शुक्ला

2014 में 'अच्छे दिन आएंगे' के नारे के साथ केंद्र की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2026 तक लगातार 12 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह भारत के स्वतंत्र इतिहास में सबसे लंबी अखंड सत्ता वाले प्रधानमंत्रियों में से एक कार्यकाल है। इस दौरान सरकार की नीतियों, योजनाओं और राजनीतिक शैली का सीधा असर आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ा है। अलग हम कल्याणकारी योजनाओं और उनके विस्तार के विषय में बात करें तो उनकी फेरहिस्त काफी लंबी है।

पिछले 12 साल में सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को आधार बनाकर योजनाओं का दायरा बढ़ाया। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण शौचालय कवरेज को तेज़ी से बढ़ाया। आयुष्मान भारत योजना ने 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा गरीब परिवारों तक पहुंचाया। जनधन खातों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया और कोविड काल में डीबीटी से करोड़ों लोगों को सीधी मदद मिली। आम आदमी के लिए इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी लाभ के लिए बिचौलियों पर निर्भरता घटी। बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ा, जिससे क्क्ष आज छोटे दुकानदार से लेकर ठेले वाले तक इस्तेमाल कर रहे हैं।

हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल भारत की तो इसमें भी प्रगति हुई है और कई सुधार अभी भी बाकी हैं। सड़क, रेल, हवाई अड्डे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेज़ी आई। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, अटल टनल, और नए वंदे भारत ट्रेनें आम यात्रियों के सफर को तेज़ और सुरक्षित बनाने की कोशिश हैं। डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच गांवों तक बढ़ी। इससे शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं मोबाइल पर आ गईं।

आम आदमी के लिए इसका फायदा समय की बचत और लागत में कमी के रूप में दिखा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी इंटरनेट की गुणवत्ता और बिजली की आपूर्ति असमान बनी हुई है। हालांकि कर और अर्थव्यवस्था में बदलाव तो हुआ है लेकिन महंगाई के कारण अभी उतनी राहत महसूस नहीं हुई है। GST लागू होने से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एकजुट हुई। छोटे व्यापारियों के लिए शुरू में जटिलता बढ़ी, लेकिन धीरे-धीरे फाइलिंग आसान हुई। नोटबंदी 2016 का मकसद काला धन और नकली नोट पर चोट था, लेकिन इसका तत्काल असर छोटे कारोबार और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और निजी निवेश की रफ्तार आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता बनी रही। कोरोना के बाद रिकवरी तेज़ रही, लेकिन असंगठित क्षेत्र में रोज़गार और आय अभी भी पूरी तरह पटरी पर नहीं आई है।

राजनीतिक संवाद और छवि की बात की जाये तो इसमें मोदी सरकार का कोई जोड़ नहीं है। मोदी की सरकार ने सीधे संवाद पर ज़ोर दिया। मन की बात, सोशल मीडिया और रैलियों के ज़रिए प्रधानमंत्री खुद जनता से जुड़े रहे। 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा केंद्र में रहा। विरोधियों का आरोप रहा कि आलोचना को जगह कम मिली और मीडिया पर नियंत्रण बढ़ा। आम आदमी के लिए इसका असर यह हुआ कि सरकार की योजनाओं की जानकारी तेज़ी से पहुंची, लेकिन विपरीत राय और स्थानीय समस्याएं कई बार राष्ट्रीय बहस में जगह नहीं बना पाई।

अलग हम इसकी ज़मीनी हकीकत जानें और यह पता करें कि क्या बदला? तो 12 साल में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सरकार सीधे नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पहले जहां फाइलों और दफ्तरों में काम अटकता था, अब ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स से काम होता है। गरीबों के लिए रसोई गैस, शौचालय, बिजली और बैंक खाता पहले से ज्यादा सुलभ हुए हैं। दूसरी तरफ, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय और शिक्षा-स्वास्थ्य की गुणवत्ता जैसे मुद्दे अभी भी चुनौती हैं। मध्यम वर्ग टैक्स और जीवनयापन की लागत को लेकर दबाव महसूस करता है। ग्रामीण भारत में कृषि पर निर्भरता और मौसम की मार अब भी जीवन को अनिश्चित रखती है। मोदी की 12 साल की सत्ता ने आम आदमी की ज़िंदगी में बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल पहुंच के मामले में ठोस बदलाव लाए हैं। योजनाओं का लाभ पहले से ज्यादा पारदर्शी हुआ है। लेकिन रोज़गार, महंगाई और असमानता जैसे संरचनात्मक मुद्दे बने हुए हैं। आम आदमी के लिए यह कार्यकाल सुविधाओं में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव दोनों का मिश्रण रहा है। 2026 की सियासत इस बात पर टिकी होगी कि क्या सरकार इन बदलावों को स्थायी रोज़गार और आय में बदल पाती है।

बचपन की मिठास को कड़वे पसीने में बदलती यह निर्दयी दुनिया

[जब तक आखिरी बच्चा श्रम से मुक्त नहीं, हम सब अपराधी हैं]

[बचपन की सबसे बड़ी विडंबना- सपनों का नहीं, मजबूरी का बड़ा होना]

किसी भी समाज का भविष्य बच्चों की आँखों में बसता है। जब उन आँखों के सपने स्कूल की चौखट तक पहुँचने से पहले ही श्रम की धूल में खो जाएँ, जब नन्हे हाथ खिलौनों और किताबों के बजाय बोझ और औजार उठाने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं मानवता हार रही है। 12 जून का विश्व बाल श्रम निषेध दिवस इसी पीड़ा की याद दिलाता है—यह उन करोड़ों बच्चों की मौन पुकार है जिनसे उनका बचपन छिन गया। तकनीकी युग में भी असंख्य बच्चे श्रम की बेड़ियों में जकड़े हैं। किसी राष्ट्र की सच्ची समृद्धि उसके सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक बचपन से मापी जाती है; बचपन असुरक्षित हो तो विकास फीका पड़ जाता है।

आँकड़े बताते हैं कि बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई अभी अधूरी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में भी दुनिया के लगभग 138 मिलियन बच्चे बाल श्रम में फँसे हुए थे, जिनमें 54 मिलियन बच्चे ऐसे खतरनाक कार्य कर रहे थे जो उनके जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए सीधा खतरा हैं। निस्संदेह, वर्ष 2000 के 246 मिलियन की तुलना में यह संख्या लगभग आधी हुई है, पर संतोष का कोई कारण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 8.7, जिसके तहत 2025 तक बाल श्रम समाप्त करने का संकल्प था, पूरा नहीं हो सका। प्रयासों ने तस्वीर बदली है, लेकिन हकीकत नहीं; जब तक आखिरी बच्चा भी श्रम से मुक्त नहीं होता, तब तक हर उपलब्धि अधूरी

रहेगी। बाल श्रम का वैश्विक भूगोल भी गहरी चिंता पैदा करता है। उप-सहारा अफ्रीका में लगभग 87 मिलियन बच्चे बाल श्रम में फँसे हैं, जो विश्व के कुल बोझ का लगभग दो-तिहाई है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में संख्या 49 मिलियन से घटकर 28 मिलियन हुई है, पर राहत अभी अधूरी है। आज भी लगभग 61 प्रतिशत बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। खेतों, बागानों और पशुपालन में खपते इन बच्चों के श्रम का हिसाब मिलता है, लेकिन उनके खोए बचपन का नहीं। घरेलू काम, छोटे कारखाने, बाजार, निर्माण स्थल और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ भी बाल श्रम के छिपे केंद्र बने हुए हैं। विडंबना यह है कि हम उत्पादों की चमक देखते हैं, पर उनके पीछे खोया बचपन नहीं।

भारत की स्थिति किसी भी तरह के आत्मसंतोष की गुंजाइश नहीं छोड़ती। आधिकारिक आँकड़ों में लाखों बच्चे बाल श्रम में दर्ज हैं, जबकि विशेषज्ञ इसे इससे कहीं अधिक मानते हैं। कृषि, पटाखा, चमड़ा, काँच उद्योग, खदानें और शहरी घरेलू कार्य—हर जगह बचपन श्रम में उलझा दिखता है। महामारी के बाद बढ़ी गरीबी, मानव तस्करी, पारिवारिक मजबूरियाँ और जलवायु संकट ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज श्रम में खोया हर बच्चा कल की प्रतिभा हो सकता था। बाल श्रम दरअसल भविष्य की संभावनाओं की चोरी है। कानून मौजूद हैं, पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन अब भी कमजोर है—एफआईआर बढ़ती हैं, लेकिन दोषसिद्धि कम।

बाल श्रम केवल अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज की नैतिक परीक्षा है। एक ओर हम बच्चों को देवतुल्य मानकर पूजते हैं, दूसरी ओर वही व्यवस्था उन्हें सबसे सस्ता श्रमिक बना देती है। गरीबी, अशिक्षा, वयस्कों के लिए रोजगार की कमी और कमजोर सामाजिक सुरक्षा—ये चार आधार बाल श्रम को मजबूती देते हैं। आजीविका के दबाव में परिवार बच्चों को भी श्रम की ओर धकेल देते हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट, संघर्ष और युद्ध जैसी वैश्विक परिस्थितियाँ उनके बचपन को और संकुचित कर रही हैं। स्पष्ट है कि समाधान केवल बच्चों को काम से हटाने में नहीं, बल्कि उन सामाजिक-आर्थिक कारणों को बदलने में है जो उन्हें वहाँ पहुँचाते हैं।

बाल श्रम के विरुद्ध अभियान में वर्ष 2026 का विषय निर्णायक संकेत देता है— 'बाल श्रम को लाल कार्डः बच्चों के लिए उचित अवसर, वयस्कों के लिए सम्मानजनक कार्य।' यह केवल नारा नहीं, बल्कि नीति परिवर्तन का आह्वान है। इसका स्पष्ट संदेश है कि बच्चों को अवसर और वयस्कों को सम्मानजनक रोजगार साथ-साथ दिए बिना बाल श्रम समाप्त नहीं होगा। फरवरी 2026 की माराकेश रूपरेखा ने भी शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सुधार पर जोर दिया है। लेकिन संकल्प तभी सार्थक हैं जब वे जमीन पर बदलाहट बनें। दुनिया ने बाल श्रम के विरुद्ध अनेक संकल्प लिए हैं; अब जरूरत घोषणाओं से आगे बढ़कर उन्हें लागू करने की है।

बाल श्रम केवल अधिकारों का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानव विकास की गहरी बाधा है। बचपन में काम करने को मजबूर बच्चा शिक्षा और कौशल से वंचित रह जाता है, जिससे आगे उसकी आय, अवसर और उत्पादकता सीमित हो जाती है और गरीबी पीढ़ियों तक चलती है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादकता, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता पर भी पड़ता है। फिर भी आशा बनी हुई है—कुछ गाँवों की सामुदायिक निगरानी, एनजीओ की पहल और राज्य स्तरीय योजनाएँ सकारात्मक संकेत दे रही हैं। लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं; जरूरत है एक व्यापक, सख्त और समन्वित अभियान की, जिसमें पारदर्शी आपूर्ति शृंखलाएँ, कानून, आर्थिक सहारा और सामाजिक जागरूकता साथ चलें। सभ्यता की असली पहचान बच्चों की हँसी में है, न कि उनके श्रम में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें याद दिलाता है कि अब संवेदना नहीं, निर्णायक कार्रवाई का समय है। बाल श्रम को हर स्तर पर वास्तविक 'लाल कार्ड' दिखाना होगा—यह जिम्मेदारी सरकार, समाज, उद्योग और हर नागरिक की है। घर से लेकर कार्यस्थल तक यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी बच्चे का श्रम हमारी सुविधा न बने। बाल श्रम से मुक्ति केवल बच्चों की नहीं, पूरी मानवता की मुक्ति है। यदि बचपन अंधेरे में खोया रहा, तो भविष्य भी अधूरा रहेगा। बच्चों को शिक्षा, खेल और सपने तथा वयस्कों को सम्मानजनक काम—यही संतुलन मानवता की असली जीत है।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

नेटफ्लिक्स पर एक हफ्ते से डेरा जमाए बैठी ये रोमांटिक ड्रामा, माधुरी दीक्षित की 'मां बहन' को दे रही कड़ी टक्कर

कई बार कुछ फिल्मों को हिट होने के लिए कोई बड़ी कास्ट या बजट की जरूरत नहीं होती। कुछ फिल्में अपनी कहानी की वजह से से भी हिट हो जाती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक इमोशनल स्टोरी के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसने आते ही ओटीटी पर तहलका मचा दिया। ये फिल्म 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब एक महीने से भी कम समय में ये ओटीटी पर आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं रोमांटिक ड्रामा फिल्म 29 की।

किन भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म

29 की कहानी एक ऐसे लड़के सत्या के बारे में जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और इस वजह से उसे सब ताने मारते हैं। सत्या का भी यही दुख है कि कोई लड़की उससे बात नहीं करती लेकिन फिर उसकी जिंदगी में विजी आती है और उसकी कहानी में रंग भर जाते हैं। इस फिल्म को रत्ना कुमार ने डायरेक्ट किया है और ये तमिल भाषा में रिलीज हुई। हालांकि नेटफ्लिक्स पर आप इसे हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु में देख सकते हैं।

कौन-कौन से कलाकार आए नजर

कास्ट की बात करें तो '29' में विधु ने सत्या, प्रीति असरानी ने विजयलक्ष्मी, महेंद्रन ने संतोष, अविनाश ने मणि, शहनाज फातिमा ने जानू और प्रेम कुमार ने कुरुनीला कथिरवन की अहम

भूमिकाएं निभाई हैं। कार्तिकेयन संथानम और लोकेश कनगराज ने 'जी स्क्वाड' के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इसे रत्ना कुमार ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के कई सीन्स बेहद इमोशनल हैं जो आपको शायद रुला भी दें। 29 को आईएमडीबी पर 7.4 रेटिंग मिली है। फिल्म इस समय नेटफ्लिक्स पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है।

नेटफ्लिक्स पर छाई ये फिल्म

हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर माधुरी दीक्षित स्टारर डार्क कॉमेडी थ्रिलर मां बहन रिलीज हुई और वह नंबर-1 के पायदान पर ट्रेंड कर रही है। लेकिन फिलहाल मां बहन की नंबर-1 की कुर्सी को एक साउथ सिनेमा की लव स्टोरी ड्रामा फिल्म 29 (29 रूम्1द्बद्ग) से कड़ी टक्कर मिल रही है। मौजूदा समय में तमिल फिल्म 29 नेटफ्लिक्स पर नंबर-2 पर ट्रेंड कर रही है और ऑडियंस की तरफ से इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है।

दैनिक राशिफल

मेष आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। शुभ रंगः लाल 7 शुभ अंकः 9

वृषभ पुराने रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें।
शुभ रंगः सफेद 7 शुभ अंकः 6

मिथुन व्यापार में लाभ के संकेत हैं। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें।
शुभ रंगः हरा 7 शुभ अंकः 5

कर्क पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं।
शुभ रंगः क्रीम 7 शुभ अंकः 2

सिंह आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
शुभ रंगः सुनहरा 7 शुभ अंकः 1

कन्या कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
शुभ रंगः हरा 7 शुभ अंकः 7

तुला दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। नई योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंगः गुलाबी 7 शुभ अंकः 6

वृश्चिक गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। नौकरी में बदलाव का विचार बन सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें।
शुभ रंगः लाल 7 शुभ अंकः 8

धनु भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शुभ रंगः पीला 7 शुभ अंकः 3

मकर कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताएं। शुभ रंगः नीला 7 शुभ अंकः 8

कुंभ नई योजनाएं लाभदायक सिद्ध होंगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।
शुभ रंगः आसमानी 7 शुभ अंकः 4

मीन मानसिक शांति बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा।
शुभ रंगः पीला 7 शुभ अंकः 7

उपाय सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और अपने इष्टदेव का स्मरण करें। इससे दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन मौन क्यों हैं?

पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के नागरिक लंबे समय से सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे हैं किंतु पाकिस्तानी सरकार अपने कब्जे वाले कश्मीरी क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के बजाय सेना के दमन चक्र से वहाँ के नागरिकों की हत्याएँ करती आई है। पाकिस्तानी हुकूमत और सेना द्वारा वर्षों से अधिकृत कश्मीरी लोगों को जबरन जेलों में बंद कर प्रताड़ित किया जाता है, उनके घरों की महिलाओं और बच्चियों की अस्मिता लूटी जाती है और विरोध के बदले मौत दी जाती है। अभी हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों द्वारा मुजफ्फराबाद में जीवनोपयोगी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु पाकिस्तानी हुकूमत से माँग की जा रही थी। पाकिस्तानी सेना को हर बार की तरह इस बार भी कश्मीरियों की माँग नागवार गुज़री और सेना प्रमुख मुनीर के इशारे पर बर्बरतापूर्वक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी लोगों पर अंधाधुंध गोलाबारी की गई, जिसमें सौ से भी अधिक लोगों की मौत होने की आशंका है।

विडंबना यह है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाकर दुनिया की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर

के लोगों की वास्तविक समस्याएँ अक्सर वैश्विक विमर्श का हिस्सा नहीं बन पातीं। वहाँ के नागरिकों को आज भी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह स्थिति पाकिस्तान के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करती है। हकीकत यह है कि पाक अधिकृत कश्मीरी लोगों के जीवन को पाकिस्तानी सेना और उसकी हुकूमत ने नारकीय बना दिया है। दुनिया में मानवता की दुहाई देने वाले अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य वैश्विक संगठनों, इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में मुसलमानों की वकालत करने वाले मौलानाओं और बात बात पर मानवता की दुहाई देने वाले मानवाधिकार संगठनों के लोगों को पाक अधिकृत कश्मीरियों पर हो रही बर्बरता क्यों नहीं नजर आती है? क्यों हर बार अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार आयोग के लोग और मौलाना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की मौत पर चुप्पी साध लेते हैं?

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के देशों और दुनिया भर के मुसलमानों के मसीहा बनने वाले ठेकेदारों द्वारा मुजफ्फराबाद में दर्जनों निर्दोष लोगों की मौत पर अफसोस जताकर पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती है? पाक अधिकृत कश्मीरियों के दर्द को दुनिया के चौधरी बनने वाले अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रखने का साहस क्यों नहीं कर पाते हैं? अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वह किसी भी क्षेत्र में मानवाधिकारों के प्रश्न पर दोहरे मापदंड न अपनाए। यदि दुनिया वास्तव में मानवाधिकारों, लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों में विश्वास करती है, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की आवाज़ को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए। वहां की परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि दुनिया वास्तव में मानवाधिकारों, लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों में विश्वास करती है, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की आवाज़ को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए। वहां की परिस्थितियों का निष्कर्ष मूल्यांकन होना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पाक अधिकृत कश्मीर जैसी किसी छोटी-सी घटना में यदि एक भी नागरिक भारतीय पुलिस या सेना द्वारा मारा जाता, तो भारत सरकार और उसकी सेना के विरोध की गूँज संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार आयोग और दुनिया भर के देशों में सुनाई देती। यही अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के देश दुनिया भर में भारत विरोधी माहौल पैदा कर देते और यही मानवाधिकार संगठन भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते फिरते। भारत लंबे समय से यह कहता आया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को भी वही अधिकार और अवसर मिलने चाहिए जो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को प्राप्त होते हैं।

ऐसे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वह क्षेत्र के लोगों के हितों को प्राथमिकता दे और किसी भी प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघन पर निष्पक्ष तथा संतुलित दृष्टिकोण अपनाए।

कश्मीर का प्रश्न केवल भू राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि वहाँ रहने वाले लाखों लोगों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर मानवता, न्याय और नागरिक अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को भय, असुरक्षा और अभाव से मुक्त जीवन मिल सके इसलिए भारत सरकार का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरी लोगों पर पाकिस्तानी फौज द्वारा की गई बर्बरता पर दर्द जताना जायज है, लेकिन भारत के इस दर्द से न तो पाकिस्तान और न ही संयुक्त राष्ट्र के देशों के कानों पर जूँ रेंगती है। अतः भारत सरकार को कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, इस सत्य को अब साकार करने का जिम्मा भारतीय सेना को देकर हमेशा-हमेशा के लिए कश्मीरियों को इस दर्द से मुक्ति दिलाने का ऐतिहासिक कदम उठाना होगा, ताकि पाकिस्तान के कश्मीरी राग का स्थायी अंत हो सके और गुलाम कश्मीरी लोगो भारतीय बनकर शांति, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सके।

अरविंद रावल

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

लखनऊ के गौतमपल्ली की क्रिश्चियन कॉलोनी के ब्यूटी पार्लर में लगी आग

लखनऊ। ब्यूटी पार्लर में शार्ट सर्किट से लगी आग ने मकान को अपनी जद में ले लिया। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की क्रिश्चियन कालोनी में गुरुवार सुबह एक मकान में संचालित ब्यूटी पार्लर में आग लग गई। आग की लपट व धुएं के बीच दो लोग फंस गए। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने दमकल को सूचना दी। आग की सूचना पर दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान चलाकर छत पर धुएं से घिरे दो लोगों को सीढ़ी की मदद से सुरक्षित नीचे उतार लिया। आग लगने के समय दो लोग भवन के अंदर फंस गए थे। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को लोहे की सीढ़ी के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे आग आसपास के हिस्सों में फैलने से बच गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि, आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। गौतमपल्ली की क्रिश्चियन कॉलोनी में 'जस्ट फॉर डिवाइस' केडीए ब्यूटी पार्लर में आग लगने की प्रारंभिक जांच में कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि पार्लर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया।

लखनऊ : सेवानिवृत्त कंप्यूटर ऑपरेटर से निवेश के नाम पर ठगे 92.50 लाख

लखनऊ। साइबर जालसाजों ने मंडी परिषद से सेवानिवृत्त कंप्यूटर आपरेटर दिनेश कुमार शर्मा से निवेश के नाम पर जाल में फंसाया। फिर उन्हें दो करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया। उसी के आधार पर धीरे-धीरे कई बार में 92.50 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने चिनहट थाने में चार ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें बलबीर मेंटर वाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा गया। ग्रुप की एडमिन साक्षी शर्मा ने खुद का कलकत्ता निवासी बताया। ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने पर सौ फीसद मुनाफा कमाने का झांसा दिया। बलबीर और साक्षी ने उनसे बाइनांस एप डाउनलोड कराई। फिर उनकी आइडी जनरेट कर दी। उनसे उनकी बैंक डिटेल ले ली। शुरुआत में उन्होंने 18.50 लाख रुपये निवेश किए। मगर उन्हें मुनाफा नहीं मिला। उन्होंने जब ठगों से मुनाफा मांगा तो उनसे आइडी एड्रेस गलत होने की बात कहीं। इसे सही करने के एवज में उनसे 29 लाख मांगे गए। इस पर दिनेश ने पेंशन के 29 लाख रुपये जमा कर दिए। फिर ठगों ने लाईबिट कस्टमर सर्विस का नंबर पीड़ित को दिया और मुनाफा मांगने को कहा। पीड़ित ने जब वहां संपर्क किया तो उनसे सेबी का खाता चालू करने के लिए 20 लाख रुपये और जमा करा लिए गए। दिनेश ने जब दोबारा रकम की मांग की तो इस बार ठगों ने उन्हें एप की आइडी लागइन का भय दिखाया और सही करने के नाम 13 लाख की फीस जमा कर ली। इसके बाद ठगों ने अपने मोबाइल नंबर भी स्विच आफ कर लिया। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि पीड़ित को ट्रांजेक्शन संबंधी दस्तावेजों के साथ बुलाया है।

गिट्टा गैंग का पर्दाफाश: लखनऊ में महिला समेत तीन शातिर चोर गिरफ्तार

सरोजनीनगर। बिजनौर पुलिस ने संगठित चोरी करने वाले कुख्यात 'गिट्टा गैंग' का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब छह लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण तथा चोरी की वारदात में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद की है। गैंग का एक सदस्य आकाश पाण्डेय उर्फ सूरज अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस के अनुसार, कमलापुर निवासी मनोज कुमार की ज्वेलरी दुकान में 2 जून की रात हुई चोरी की घटना के खुलासे के क्रम में की गई। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। इस संबंध में बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। गुरुवार को किसान पथ अंडरपास के पास सर्विस रोड से निलोफर उर्फ गिट्टा उर्फ गीता (22), प्रियांशु उर्फ दीपांशु (20) और अमन (22) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लंबे समय से बंद दुकानों और मकानों की रेकी कर शटर काटकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी के बाद वे सुनसान स्थानों पर माल का बंटवारा कर लेते थे। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में आभूषण बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरी की घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की स्कूटी भी जब्त की गई है। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बताया कि, 'कमलापुर ज्वेलरी चोरी प्रकरण के खुलासे के लिए गठित टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिट्टा गैंग का खुलासा किया गया है। गैंग का एक सदस्य अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल के साथ सरचार्ज के प्रस्ताव पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा नाराज

● पावर कारपोरेशन के चेयरमैन से मांगा स्पष्टीकरण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल के साथ दस प्रतिशत सरचार्ज का प्रकरण बेहद गंभीर होता जा रहा है। बिजली महंगी करने के प्रकरण में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से अनुमति भी नहीं ली गई। टीवी समाचार से इसकी जानकारी होने पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का गुस्सा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल पर फूट पड़ा है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली बिल महंगे करने के फैसले और अन्य मुद्दों पर गोयल से सख्त लहजे में सवाल पूछा है। मंत्री ने चेयरमैन को पत्र लिखकर पूछा है कि बिना उन्हें विश्वास में लिए ऐसे फैसले कैसे लिए गए और जनता के बीच सरकार की छवि खराब क्यों की गई। उन्होंने पत्र लिखकर पूछा है कि बिजली बिल महंगा करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले को लेकर उनसे पूछना तक भी उचित नहीं समझा गया। बिजली के बिल पर 10 प्रतिशत पावर परचेज सरचार्ज का विवाद उपभोक्ता परिषद के विरोध पर पहले विद्युत नियामक आयोग पहुंचा। अब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल से बेहद खफा हैं। मंत्री एके शर्मा ने चेयरमैन को पत्र लिखकर कड़े सवाल किये हैं। उन्होंने जून 2026 में पावर परचेज सरचार्ज के नाम दस प्रतिशत के अधिभार लगाने के फैसले पर पूछा है कि उन्हें क्यों नहीं बताया गया। ऊर्जा मंत्री ने पूछा है कि बिना उन्हें बताए और बगैर अनुमति के यह फैसला कैसे लिया गया। मंत्री एके शर्मा ने कहा कि आपके कई फैसले तो मुझे टीवी न्यूज चैनल से पता चलते हैं। विभाग के फैसले मुझे मीडिया से पता चलते हैं।

गलत फैसले से सरकार की किरकिरी

यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपने लेटर में पूछा है कि बिजली महंगी करने के फैसले की वजह से सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि सोशल मीडिया से भी मुझे भी जानकारी हुई है. ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर फैसले से पहले विभाग के मंत्री से ही अनुमति तो दूर जानकारी देना भी उचित नहीं समझा गया।

कुशल कर्मचारियों की छंटनी पर भी सवाल

ऊर्जा मंत्री ने गोयल को पत्र में लिखा 'मेरे बार-बार मना करने के बाद भी कुशल कर्मचारियों की छंटनी बंद नहीं की गई। मनमाने ढंग से कुशल कर्मचारियों को हटाकर अकुशल लोगों की भर्ती की जा रही है। जिसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है। एक मई 2026 को सहारनपुर मंडल उपाध्यक्ष अंकुर सैनी ने एक मामले को संज्ञान में लाया था। उन्होंने बताया था कि 15 वर्ष से कार्यरत लाइनमैन सुंदर सैनी को हटाकर नए लाइनमैन को रख लिया गया। इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। लाखों उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो और रिपेयरिंग और रेस्टोरेशन की व्यवस्था के लिए 30 मई को समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जानकारी मिली की ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी आप हेडक्वार्टर से बाहर हैं।

पीस कमेटी की बैठक में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली परिसर में बृहस्पतिवार को आगामी मोहर्रम पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, ताजियादारों और विभिन्न समुदायों के लोगों ने भाग लिया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि मोहर्रम आस्था और अनुशासन का पर्व है। सभी लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व मनाएं। उन्होंने अफवाहों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था भंग करने या कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी होने पर तुरंत पुलिस को देने को कहा। इस अवसर पर प्रधान महखेड़ा अब्दुल नसीम, ओम प्रकाश, मो. इस्माइल, महमूद अली, प्रदीप, नूर मोहम्मद, गुड्डू, असलम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

स्टेशन रोड पर मामूली बात को लेकर युवक को पीटा

● मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के स्टेशन रोड पर बुधवार देर रात एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला निवासी छोटू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार रात करीब 11:30 बजे उसकी पत्नी गुंजन, साली संध्या, साढ़ू नीरज तथा अभिषेक ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि सभी ने लात-घूंसों और सरिया से हमला कर उसे घायल कर दिया। मारपीट में छोटू को गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की चर्चा है। हालांकि स्वतंत्र प्रभात वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को दिया समर्थन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 11 जून पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली को लेकर चल रहे आंदोलन को नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन ने अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। गुरुवार को काकोरी शहीद स्थल, लखनऊ से अटेवा ओल्ड पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जन जागरण रथ यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएमओपीएस एवं प्रदेश अध्यक्ष अटेवा विजय कुमार 'बंधु' के नेतृत्व में किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष लता सचान, उपाध्यक्ष सुजान सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी मनोज वर्मा तथा प्रचार मंत्री भानु प्रताप सिंह ने सहभागिता कर पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और इसकी बहाली के लिए चल रहे संघर्ष में संगठन पूरी निष्ठा और मजबूती के साथ सहभागी रहेगा। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन तन, मन और धन से अटेवा के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के साथ खड़ा है तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगा। पदाधिकारियों ने प्रदेश भर के कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी कर्मचारी एकजुट होकर अपना योगदान दें और अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूती प्रदान करें।

बसपा की 2027 चुनाव रणनीति, यूपी में पिछड़ों को साधने की कवायद तेज

लखनऊ। विधान सभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा, पिछड़ों में पैठ बढ़ाने की कोशिश तेज करने जा रही है। बुधवार को माल एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय पर हुई पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं को रणनीति समझाई गई। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कमेटियों को व्यापक जनसंपर्क करने और संगठन के विस्तार के निर्देश दिए। वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव के लिए बसपा अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें अपने पुराने दलित वोट को तो मजबूत किया ही जा रहा है, सवर्णों खासकर ब्राह्मणों को भी जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी पिछड़े वर्गों में भी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम रही है। इसके लिए प्रदेश भर में भाईचारा कमेटियों को लगाया गया है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों पर है। बुधवार को हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने भाईचारा कमेटियों से अब तक किए काम के संबंध में जानकारी ली। निर्देश दिए कि कि स्थानीय स्तर पर समाज के बीच छोटी-छोटी बैठक कर पार्टी की विचारधारा का विस्तार किया जाए। समाज से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाए।

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की लहरपुर इकाई ने व्यापारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लहरपुर- सीतापुर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तहसील परिसर में आयोजित व्यापारियों एवं उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी.) की लहरपुर इकाई ने व्यापारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन नगर अध्यक्ष रियाज अहमद (बबलू) के नेतृत्व में सौंपा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही रहे, जबकि कार्यक्रम का आयोजन तहसीलदार मनीष त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने व्यापारियों की सुरक्षा, बाजार में, पार्किंग व्यवस्था, आपात स्थिति में अग्निशमन सुविधा तथा प्रशासनिक सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा प्रशासन एवं व्यापारियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक माह नियमित बैठक आयोजित की जाए। इसके अतिरिक्त प्रमुख बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पिंक शौचालयों का निर्माण, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था तथा अग्निशमन सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई। व्यापार मंडल ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि यदि किसी व्यापारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे अनावश्यक रूप से प्रताड़ित न किया जाए, बल्कि सम्मानपूर्वक थाने बुलाकर आवश्यक पूछताछ की जाए दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाए । साथ ही साप्ताहिक बंदी का शनिवार को पूर्ण पालन सुनिश्चित कराने, नगर के विकास एवं व्यापारिक हितों से जुड़े मामलों में संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करने का अनुरोध भी किया गया । व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण वितरण का उल्लेख करते हुए व्यापार एवं उद्योग गतिविधियों को और अधिक सुगम बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की मांग की। अंत में व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी से सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा व्यक्त की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नगर अध्यक्ष रियाज अहमद (बबलू), महामंत्री हरीश रस्तोगी (गोलू), वीरेन्द्र पुरी, विभूति पुरी, अशरफ बिलाल, उपाध्यक्ष मो. हाशिम अंसारी, जावेद अंसारी, निहाल कुरैशी, कोषाध्यक्ष ओमकार जायसवाल, सगीर अहमद, दीपक रस्तोगी, रेहान अहमद, शरीफ अहमद, आशिक अली, प्रदीप सिंह, सियाराम जायसवाल, सतीश जायसवाल, मोहम्मद अकरम, इश्तियाक अहमद, मो. लुकमान, आमिर चौधरी, सलीम, शमशुल हसन, सरोज जायसवाल, जितिन चौरसिया, लुकमान, आमिर चौधरी, मो0 आरिफ सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

मंदिरों में पूजा कर की गई मोदी की लंबी उम्र की कामना

● भाजपा सभासद मनीष शुक्ला के आवास पर आयोजित हुई गोष्ठी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लहरपुर (सीतापुर)- भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल के लगातार बारह वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश मे आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों के क्रम मे निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा के नेतृत्व मे स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही शिव मन्दिरों मे जलाभिषेक व रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लम्बी आयु की कामना की।इसके बाद उन्होने नगर के विभिन्न वार्डो मे भ्रमण कर जगह-जगह गोष्ठी की। इसी क्रम मे नगर के मोहल्ला गन्नी टोला स्थित भाजपा सभासद मनीष शुक्ला के आवास पर आयोजित गोष्ठी को सम्बोधित करते हुये निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा ने आम जनता को सरकार द्वारा पिछले बारह वर्षो मे किये गये उल्लेखनीय कार्यो और वर्तमान मे चलाई जा रहीं जन-कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। उन्होने कहा कि यह कार्यक्रम लगातार पांच दिनों तक चलेगा जिसमे आज प्रथम दिन नगर मण्डल क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और शेष चार दिनों में देहात क्षेत्र के सभी मण्डलों का भ्रमण कर व्यापक रूप से जनसम्पर्क अभियान को पूरा किया जायेगा। इस अवसर पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य वीरेंद्र पुरी, भाजपा जिला मंत्री मनोज गुप्ता, नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल, नामित सभासद देवेष अवस्थी, रामे बाजपेई, मनमोहन गुप्ता, बंशीधर पाठक, पंकज शुक्ल, कमलकिशोर शुक्ल, धर्मेद्र पाण्डेय, दिनेश शुक्ल, अजय शुक्ल, राजेश अवस्थी, ब्रजकिशोर शुक्ल, मनोज तिवारी , प्रांजुल मिश्रा प्रमुख रुप से उपस्थित रहे।

खेत में ट्यूबवेल पर सो रहे 48 वर्षीय व्यक्ति की सिर कुचलकर निर्मम हत्या से मचा हड़कंप

● प्तघटना की जांच में जुटी पुलिस जल्द ही खुलासे का दिया आश्वासन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली- गुरबक्शगंज थाना क्षेत्र के अटौरा बुजुर्ग चौकी अंतर्गत पूरे निधि गांव के पास मालिन बाग में गुरुवार सुबह 48 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई मृतक की पहचान अटौरा निवासी शंभू उर्फ छेद्दू पुत्र भगौती के रूप में हुई है परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, छेद्दू बीते 5 दिन पूर्व ही ईट भट्ठे से मजदूरी कर घर वापस लौटा था बुधवार रात वह खाना खाकर गांव के बाहर स्थित अपने ट्यूबवेल पर सोने चला गया गुरुवार सुबह करीब 8 बजे जब परिवार का ही अमरनाथ खेत में पानी लगाने पहुंचा तो ट्यूबवेल के पास मालिन बाग में छेद्दू का शव पड़ा देख उसके होश उड़ गए उसने तुरंत शोर मचाकर परिजनों को सूचना दी सूचना पाते ही गांव के काफी लोग घटनास्थल पर पहुंच गए शंभू की इस तरह से निर्मम हत्या से सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए की आखिर शंभू की हत्या किसने कर दिया फिलहाल परिवारिक जनों ने तहरीर में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही अटौरा बुजुर्ग चौकी पुलिस और गुरबक्शगंज थाने की फोर्स मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए परिवारिक जनों से बातचीत कर तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुड़ाते हुए शीघ्र ही घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी करने का आश्वासनदिया है।

लखनऊ : युवक को बंधक बनाकर लोहे की रॉड से पीटा, हालत गंभीर; आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस

लखनऊ। बीबीडी इलाका स्थित बीसीसी शक्ति अपार्टमेंट में युवक को वहीं रहने वाले युवकों ने बंधक बनाकर पीटा। पीड़ित के पिता ने अपार्टमेंट में रहने वाले एक युवक और उसके साथियों पर बंधक बनाकर पीटने, मोबाइल तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने की तहरीर स्थानीय थाने में दी। इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तिवारीगंज स्थित बीसीसी शक्ति अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर-814 निवासी पंकज यादव के मुताबिक, सात जून की रात उनका बेटा मयंक दैनिक उपयोग का सामान लेकर लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। इसी दौरान फ्लैट नंबर-401 में रहने वाले विपिन कुमार सिंह अपने साथियों अनुराग मिश्रा, अभि ठाकुर और राज मिश्रा के साथ वहां पहुंचे और उनके बेटे को धक्का दे दिया। आरोपितों ने उनके बेटे को लिफ्ट से बाहर खींच लिया। गालियां दी, करीब 20 मिनट तक बंधक बनाकर पीटा। लोहे के पाइप से हमला किया गया। सिर व शरीर के कई हिस्सों में चोट आई हैं। मोबाइल भी तोड़ दिया। बेहोश होने पर उस पर पत्थर से वार किया गया। पिता ने बताया कि आरोपित अपराधी हैं। पूरा परिवार दहशत में है। इंस्पेक्टर राम सिंह के मुताबिक सीसी फुटेज की मदद से मामले में साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं।

भीषण गर्मी और लू पर भारी पड़ा कर्तव्य: मोहनलालगंज के राजेश मिश्रा बने लोकतंत्र के सच्चे सिपाही

● .....45 डिग्री तापमान में भी गांव-गांव घूमकर संवार रहे मतदाता सूची, ग्रामीणों के लिए बने प्रेरणा का स्रोत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों आसमान से बरसती आग, रिकॉर्ड तोड़ते तापमान और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों ने जहां आम जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर एक अनोखा जज्बा देखने को मिल रहा है। मोहनलालगंज क्षेत्र के भौदरी में तैनात सरकारी कर्मचारी राजेश मिश्रा इस भीषण गर्मी में भी कर्तव्यनिष्ठा की एक बेमिसाल इबारत लिख रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत, राजेश मिश्रा लगभग 45 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा धूप में भी बिना थके, बिना रुके दिन-रात अपने दायित्वों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। जब दोपहर के वक्त गर्मी अपने चरम पर होती है और लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तब राजेश मिश्रा सिर पर छतरी ताने और पानी की बोतल थामे क्षेत्र के विभिन्न गांवों में घर-घर दस्तक देते नजर आते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना, पुरानी त्रुटियों को सुधारना और पूरी सूची को पारदर्शी व त्रुटिहीन बनाना है। राजेश मिश्रा की यह मुहिम सिर्फ कागजी काम तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा रहे हैं। अपने अत्यंत विनम्र, सौम्य और सहयोगी स्वभाव के कारण वे बहुत कम समय में ग्रामीणों के चहेते बन गए हैं। वे गांव के हर परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। विशेषकर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को नए मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ, वे घर की महिलाओं और बुजुर्गों को भी मतदान के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके एक-एक वोट के महत्व के प्रति जागरूक कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी राजेश मिश्रा की ऐसी लगन और मेहनत सचमुच वंदनीय है। उनके इस अद्वितीय समर्पण की बदौलत न केवल क्षेत्र की मतदाता सूची अधिक शुद्ध और सटीक हो रही है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर एक नई चेतना भी जागी है। भीषण गर्मी के बीच उनकी यह असाधारण कर्मठता आज न केवल प्रशासन के लिए गर्व का विषय है, बल्कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कर्तव्यपरायणता की एक बेहतरीन मिसाल बन चुकी है।

श्री रोहिताय शिव मंदिर का मनाया गया तीसरा स्थापना दिवस, पीत वस्त्रों में निकली कलश यात्रा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवा (सीतापुर)- कस्बा स्थित श्री रोहिताय शिव मंदिर का वृहस्पतिवार 11 जून को तीसरा स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूम धाम के साथ मनाया गया जिसमें गाजे बाजे के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कलशयात्रा निकाली गई जो मंदिर से चलकर कस्बे में भ्रमण करती हुई उत्तर किनारे पर बह रही पतित पावनी केवानी नदी के तट पर पहुंची और वहां से मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरकर उसे सिर पर रखकर वापस मंदिर आई जिसमें भारी संख्या में कस्बा व मुहल्ले की महिलाएं, बच्चे व पुरुष शामिल रहे। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के छठवान, मवासेपुर, मीनापुर, फरदापुर, गनुवापुर, पिपरा खुर्द, अहरोरी सहित रेउसा और बिसवां आदि स्थानों के श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पर पहुंच गये थे। मंदिर पहुंचने पर पुजारी पं0 उमेश कुमार गौड़ व सुरेश प्रकाश गौड़ ने भगवान शिव का मंत्रोच्चार के बीच जलाभिषेक और पूजन आरती कराया। इस मौके पर भगवान भोलेनाथ के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। शाम को मंदिर पर विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने देर रात तक भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मुख्य यजमान राकेश कुमार नंद, राजेश कुमार नंद, सुरेश प्रकाश विश्वकर्मा,शिव कुमार विश्वकर्मा,नीरज नंद, विशाल नंद, प्रशांत श्रीवास्तव (लवी), शशांक श्रीवास्तव (अमन), संदीप नंद, राजीव नंद, नमन गौड़, मनोज गौड़, हरिनाम वर्मा व बैजनाथ वर्मा, संतोष वर्मा, हरगोविंद वर्मा,उत्तम सिंह, शिवकुमार गुप्ता, अक्षत श्रीवास्तव, समर्थ श्रीवास्तव, लक्ष्य श्रीवास्तव,पांखी श्रीवास्तवा व सहित सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। रात्रि में श्री खाटू श्याम संकीर्तन होगा।

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली सरकार 39 जन कल्याणकारी शिविर लगाएगी, लोगों को एक ही जगह मिल सकेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके अंतर्गत मोदी सरकार के साथ ही दिल्ली की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा 18 से 20 जून तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। सभी विभागों को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई।

सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करना उद्देश्य

अधिकारियों को शिविरों में आने वाले नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवश्यक सेवा और सहायता एक ही स्थान पर सरल एवं प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने को कहा गया है। मंत्री ने कहा कि जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करना है।

नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश

यह सुनिश्चित किया जाना है कि पात्र नागरिकों को किसी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। ये शिविर केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि जनता के साथ सीधे संवाद और समस्याओं के समाधान का भी एक महत्वपूर्ण मंच हैं। सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, समाज कल्याण, विद्युत, श्रम, राजस्व परिवहन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, विधि, न्याय एवं विधायी मामले सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

पर्यावरण अपराधों की भी राजधानी बनी दिल्ली, 91% मामले लंबित

नई दिल्ली। दिल्ली न सिर्फ प्रदूषण और कचरे के मोर्चे पर जूझ रही है, बल्कि पर्यावरण संबंधी कानूनों को तोड़ने के मामलों में भी काफी संवेदनशील स्थिति में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की नई रिपोर्ट ''स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 : इन फिगर्स'' के अनुसार, दिल्ली पर्यावरण अपराधों की भी राजधानी बन गई है। आंकड़े बताते हैं कि इन मामलों में कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अदालतों में केस लंबित होने की दर भी डराने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले कुल पर्यावरण अपराधों में अकेले दिल्ली की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से भी ज्यादा है। यहां अवैध रूप से पेड़ काटने, फैक्ट्रियों का केमिकल बहाने, निर्माण स्थलों पर नियमों के खिलाफ धूल उड़ाने, प्रतिबंधित प्लास्टिक या ई-कचरा डंप करने, रात में तेज आवाज में लाउडस्पीकर तथा जनरेटर चलाने के मामले साल दर साल 12 से 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में दिए आंकड़ों के अनुसार, हैरानी की बात यह भी कि दिल्ली की अदालतों में पर्यावरण से जुड़े 91 प्रतिशत से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। यानी कानून तोड़ने वालों पर समय से कार्रवाई ही नहीं हो पाती। इसके अलावा, ढीली पैरवी और वैज्ञानिक सबूतों की कमी के चलते कोर्ट से सजा होने की दर 18.5 प्रतिशत से भी कम है। इसका सीधा मतलब यह कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हर पांच में से चार आरोपी साक्ष्यों के अभाव में साफ बच निकलते हैं। पर्यावरणविदों का साफ कहना है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और वन विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों में स्टाफ की कमी और स्पेशल कोर्ट में मुकदमों की कछुआ चाल के कारण ही आज राजधानी में पर्यावरण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

वैभव सूर्यवंशी का तूफान नहीं आया काम, अफगानिस्तान ने भारत को दी शिकस्त

● ट्राई सीरीज के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को अफगानिस्तान टीम के हाथों ष्टरुस् मैथड से 4 रन से हार का सामना करना पड़ा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली। ट्राई सीरीज के अपने दूसरे मुकाबले में गुरुवार को भारतीय ए टीम को अफगानिस्?तान ए टीम के हाथों DLS मैथड से 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण इस मैच को कई बार रोकना पड़ा। पहले मैच 49-49 ओवर का हुआ। भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, रुतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा की पारियों की बदौलत 49 ओवर में 9 विकेट खोकर 349 रन बनाए। जवाब में अफगान टीम ने 25.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 177 रन बना लिए थे। इसके बाद बारिश के कारण मैच रुका और फिर शुरू नहीं हो पाया।

वैभव ने दी तेज शुरुआत

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत दमदार रही। वैभव सूर्यवंशी ने आते ही अफगानी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। प्रभसिमरन सिंह का भी उन्हें भरपूर साथ मिला। दोनों के बीच 43 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली। फिफ्टी की ओर बढ़ रहे वैभव की पारी पर 8वें ओवर में ब्रेक लगा। 15 साल के बल्लेबाज ने 9 चौकों की मदद से 22 गेंदों पर 44 रन कूट दिए। 3 नंबर पर उतरे प्रियांश आर्य (8) सस्ते में आउट हो गए।

रुतुराज की फॉर्म जारी रही

पिछले मैच के के शतकवीर रुतुराज गायकवाड़ ने सिंह के साथ फिर पारी को संभाल और 79 रन जोड़े। 22वें ओवर में प्रभसिमरन कैच आउट हुए। उन्होंने 69 गेंदों पर 84 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज ने 14 चौके भी लगाए। इसके बाद रुतुराज और कप्तान तिलक वर्मा ने 66-66 रन की पारी खेली। आयुष बदोनी गोल्डन डक पर आउट हुए।

अब्दुल्ला ने खोला पंजा

अंत में सूर्यांश शेडगे ने 27 गेंदों पर 40 और अनुकूल रॉय ने 8 गेंदों पर 16 रन की पारी खेलकर भारत के स्कोर को 350 के करीब पहुंचाया। अफगानिस्तान की ओर से अब्दुल्ला अहमदजई ने पंजा खोला। वहीं फरमानुल्लाह साफी के खाते में 3 विकेट आए।

बारिश के कारण कम हुआ टारगेट

बारिश के कारण अफगानिस्तान की पारी शुरू होने में देरी हुई। अफगानिस्तान को 38 ओवर में 294 रन का टारगेट मिला। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम को सलामी जोड़ी ने तेज शुरुआत दी। कप्तान इमरान मीर और हसन ईसाखिल ने 48 गेंदों पर 63 रन जोड़े। हालांकि, इसके बाद टीम को 2 झटके लगे। 8वें ओवर में अरशद खान ने हसन को विप्रज के हाथों कैच आउट कराया। 10वें ओवर में अनुकूल रॉय ने खालिद तनीवाल को LBW आउट किया। 25.5 ओवर तक अफगान टीम ने 2 विकेट खोकर 177 रन बना लिए थे। इमरान मीर 75 और बाहिर शाह 51 रन बनाकर नाबाद थे। इस बीच बारिश के कारण एक बार फिर मैच को रोकना पड़ा। इसके बाद मैच फिर शुरू ही नहीं हुआ। अंत में DLS मैथ्ड से अफगान टीम को विजयी घोषित किया गया। इमरान मैच के हीरो रहे।

अमृतसर की सर्जन बहू डॉ. शिवांशी ने रचा इतिहास, मिसेज इंडिया के टॉप-10 में बनाई जगह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमृतसर। बिहार के पूर्णिया से निकलकर चिकित्सा जगत में अपनी पहचान बनाने वाली और अमृतसर की बहू 29 वर्षीय डॉ. शिवांशी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिसने न केवल उनके परिवार बल्कि दो राज्यों के लोगों को गर्व से भर दिया है। गुरु नानक देव अस्पताल, अमृतसर में जनरल सर्जरी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में सेवाएं दे रहीं डॉ. शिवांशी ने प्रतिष्ठित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता के टॉप -10 फाइनलिस्ट में जगह बनाई है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि एक सर्जन का जीवन बेहद व्यस्त और चुनौतीपूर्ण होता है। घंटों तक अपरेशन थिएटर में खड़े रहना, मरीजों की जिम्मेदारी निभाना, आपातकालीन ड्यूटी करना और लगातार पढ़ाई करते रहना किसी भी डॉक्टर की दिनचर्या का हिस्सा होता है। ऐसे में अपने सपनों और शौक के लिए समय निकालना आसान नहीं होता। लेकिन डॉ. शिवांशी ने यह साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। पूर्णिया (बिहार) से संबंध रखने वाली डॉ. शिवांशी ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई नेपाल के धरान से पूरी की, जबकि एमएस (जनरल सर्जरी) की डिग्री सरकारी मेडिकल कालेज, अमृतसर से प्राप्त की। इसी वर्ष 6 फरवरी 2026 को उनका विवाह अमृतसर में हुआ। शादी के बाद फरवरी महीने में ही उन्हें मिसेज इंडिया प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया और इसके बाद ऑडिशन, इंटरव्यू तथा कई कठिन चरणों से गुजरते हुए देशभर की प्रतिभागियों के बीच अपनी जगह बनाते हुए टॉप-10 में चयनित हो गईं। शिवांशी बताती हैं कि यह सफर आसान नहीं था। अस्पताल की जिम्मेदारियों और प्रतियोगिता की तैयारियों के बीच संतुलन बनाना उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। कई बार ड्यूटी खत्म होने के बाद देर रात तक तैयारी करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना है कि यदि किसी महिला में कुछ हासिल करने का जुनून और दृढ़ संकल्प हो, तो वह हर बाधा को पार कर सकती है। उन्होंने कहा कि मिसेज इंडिया के टॉप-10 में पहुंचना उनके लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता का पड़ाव नहीं, बल्कि वर्षों पुराने सपने के साकार होने जैसा है। अब जुलाई महीने में जयपुर में होने वाले ग्रैंड फिनाले में देश की टॉप-10 प्रतिभागियों में से विजेता का चयन किया जाएगा। ऐसे में बिहार के पूर्णिया की बेटी और अमृतसर की बहू डॉ. शिवांशी पर दोनों शहरों की उम्मीदें टिकी हैं।

ऑडी पदाधिकारी और चौकीदार के निलंबित थानाध्यक्ष पर भी गाज की तैयारी

● बिट्टू मौत कांड में कार्रवाई तेज, एसपी ने डीआईजी को भेजी थानाध्यक्ष के निलंबन की अनुशंसा

परिजन बोले- सभी दोषियों पर हो कार्रवाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुपौल- सुपौल जिले के जदिया थाना हाजत में बंद युवक बिट्टू कुमार की फंदे से लटककर हुई मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज होती जा रही है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पहले ड्यूटी पर तैनात ऑडी पदाधिकारी और चौकीदार को निलंबित किया गया, वहीं अब थानाध्यक्षनंद किशोर नंदन के खिलाफ भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। पुलिस अधीक्षक शरथ आर.एस. ने बुधवार को कार्रवाई करते हुएघटना के समय ड्यूटी पर तैनात ऑडी पदाधिकारी एसआई सोभरन कुमार एवं चौकीदार अनमोल कुमार पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में दोनों पर ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इसी लापरवाही के कारण हिरासत में बंद युवक की जान चली गई। एसपी शरथ आर एस ने जदिया थानाध्यक्ष नंदकिशोर नंदन के निलंबन के लिए डीआईजी को अनुशंसा भेज दी है। ऐसे में थानाध्यक्ष के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है। गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए एसपी शरथ आर.एस. ने बताया किमंगलवार की रात ड्यूटी पर तैनात एसआई सोभरन कुमार और एक चौकीदारअनमोल कुमार पासवान को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही थानाध्यक्ष के निलंबन के लिए डीआईजी को अनुशंसा भेज दी गई है। इधर, मृतक बिट्टू कुमार के परिजन अब भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक घटना के सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सकेगा। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की मांग की है। वहीं क्षेत्र के लोगों की नजर अब पुलिस विभाग की अगली कार्रवाई और पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। लोगों का मानना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस चर्चित मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी। इस बीच प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ फेरबदल किए गए हैं। जदिया थाना में पदस्थापित मुंशी मनोज कुमार का तबादला पुलिस केंद्र, सुपौल कर दिया गया है। वहीं एसआई रिंकी कुमारी को निर्मली थाना स्थानांतरित किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारी लंबे समय से जदिया थाना में कार्यरत थे, जिसके आधार पर यह नियमित प्रशासनिक कार्यबाही की गई है।

दिल्ली दंगाः अंकित शर्मा हत्याकांड में आज आ सकता है फैसला, 6 साल पुराने चर्चित मामले पर टिकी निगाहें

दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में आज कड़कड़डूमा कोर्ट फैसला सुना सकती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगी। वर्ष 2020 में हुई इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था और यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। 26 फरवरी 2020 को चांदबाग क्षेत्र स्थित एक नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद हुआ था। उस समय उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और पथराव की घटनाएं हो रही थीं। अंकित शर्मा 25 फरवरी की शाम अपने घर के पास लापता हो गए थे। अगले दिन उनका शव मिलने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। जांच के दौरान पुलिस ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपितों के खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष का दावा है कि दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या की गई और बाद में शव को नाले में फेंक दिया गया, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज किया है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सभी की नजर अदालत के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है।

सेंट्रल जेल, अमृतसर के ट्रांजिट कैंप में बंद 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमृतसर- इंसानियत और लोगों की भलाई के लिए एक पहल के तहत, सेंट्रल जेल, अमृतसर के ट्रांजिट कैंप में बंद 2 महिलाओं समेत 9 बांग्लादेशी नागरिकों को कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद 11.06.2026 को उनके अपने-अपने देशों में सफलतापूर्वक वापस भेज दिया गया। वापस भेजे गए लोगों ने 11.06.2026 को सुबह करीब 4:00 बजे सेंट्रल जेल, अमृतसर से अपनी यात्रा शुरू की। तय प्रक्रिया के मुताबिक, उनकी सुरक्षित आगे की यात्रा के लिए उन्हें ज़रूरी सुविधाएँ और मदद दी गई। करीब 30 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद, वे बांग्लादेश बॉर्डर पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें आगे की ज़रूरी कार्रवाई के लिए उनके अपने-अपने देशों के संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। यह ज़रूरी ऑपरेशन श्रीमती जतिंदर कौर, माननीय डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज-कम-चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर के अच्छे गाइडेंस और सुपरविज़न में पूरा किया गया। इस वापसी प्रोसेस को सफल बनाने के लिए, श्री अमरदीप सिंह बैंस, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर ने संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट किया और कोशिश की ताकि ये लोग जल्द से जल्द अपने वतन लौट सकें और अपने परिवारों से मिल सकें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर ने लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी एक्ट, 1987 के मकसद के मुताबिक, विदेशी नागरिकों समेत सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने में एक्टिव भूमिका निभाई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर ने इन लोगों के मामलों पर नज़र रखी, ज़रूरत पड़ने पर कानूनी मदद दी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके वापसी प्रोसेस को तेज़ करने की कोशिश की। यह पक्का किया गया कि उनके साथ पूरी इज्ज़त और इंसानी सेंसिटिविटी के साथ पेश आया जाए। इस सफल वापसी प्रोसेस में जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अहम भूमिका निभाई। राजीव कुमार अरोड़ा, सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल जेल, अमृतसर और नविंदर सिंह, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल जेल, अमृतसर ने सभी ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मैलिटीज़ को पूरा करने और इन लोगों के आसानी से जाने में पूरी मदद की। जेल डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर इस काम को आसानी से और इंसानी तरीके से पूरा किया। इनमें से कई लोगों के लिए, यह वापसी अनिश्चितता और अपने परिवारों से लंबे समय तक अलग रहने के समय के खत्म होने का संकेत है।

यह पहल न केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का मामला है, बल्कि इंसानी दया, संवेदनशीलता और व्यक्तिगत सम्मान को महत्व देने का भी एक उदाहरण है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, जेल डिपार्टमेंट और अन्य संबंधित अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से, ये लोग अपने परिवारों के साथ फिर से मिल पाए हैं और नई उम्मीद के साथ जीवन शुरू कर पाए हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, अमृतसर जरूरतमंद लोगों को न्याय, इंसानी सम्मान की सुरक्षा और कानूनी मदद देने के अपने वादे को जारी रखे हुए है।

दिल्ली को हरा-भरा बनाने की तैयारी, करीब एक हजार एकड़ क्षेत्र में 23 लाख पौधे लगाएगा डीडीए

दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) राष्ट्रीय राजधानी में पौधारोपण अभियान शुरू करने जा रहा है। एक बड़े शहरी वनीकरण कार्यक्रम के तहत दिल्ली के लगभग 1,000 एकड़ (करीब चार वर्ग किमी) क्षेत्र में लगभग 23 लाख स्थानीय पौधे लगाए जाएंगे। यह निर्णय हाल ही में एलजी तरनजीत सिंह संधू द्वारा ली गई एक समीक्षा बैठक के बाद आया है। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें डीडीए के 675 पार्क, चार प्रमुख रिज क्षेत्र (साउथ सेंट्रल रिज, नानकपुरा रिज, सेंट्रल रिज, नार्दर्न रिज) और छह जैव विविधता पार्क शामिल हैं। इस अभियान के जरिए दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.9 प्रतिशत हिस्सा इस केंद्रित शहरी वनीकरण और पारिस्थितिक बहाली कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। इस मेगा अभियान की शुरुआत जुलाई 2026 के पहले सप्ताह से होगी और यह सितंबर के मध्य तक जारी रहेगा। अभियान में ऐसे स्थानीय पेड़ों और झाड़ियों को लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो दिल्ली के मौसम के अनुकूल हों। इससे न केवल जैव विविधता बढ़ेगी, बल्कि कार्बन सोखने की क्षमता में सुधार होगा, भूजल स्तर रिचार्ज होगा एवं दिल्ली की हवा साफ होगी। डीडीए ने इस अभियान के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत जमीन चिन्हित करना, मिट्टी तैयार करना, गड्ढे खोदना और सिंचाई की व्यवस्था करना शामिल है। पौधों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं, ताकि पौधों के जीवित रहने की दर को सुनिश्चित किया जा सके।

फास्ट फ़ैशनः रनवे से बर्बादी तक एंजल शर्मा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आज के उपभोक्तावादी दौर में, जहाँ सामाजिक मीडिया, प्रभावशाली व्यक्तियों की संस्कृति और ऑनलाइन पहचान का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, फैशन के रुझान बेहद तेजी से बदल रहे हैं। नए-नए डिज़ाइन और पहनावे हर दिन सामने आते हैं और कुछ ही समय में गायब भी हो जाते हैं। इसी तेज़ी और लगातार बदलाव की मांग को पूरा करने के लिए कपड़ा उद्योग बड़े पैमाने पर कम कीमत वाले कपड़ों का उत्पादन करता है। इस प्रवृत्ति को 'फास्ट फ़ैशन' कहा जाता है।फास्ट फ़ैशन केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्कृति बन चुकी है जिसमें लोग अपनी पसंद या रचनात्मक अभिव्यक्ति के बजाय बदलते रुझानों के साथ बने रहने के दबाव में कपड़े खरीदते हैं। सामाजिक मीडिया पर प्रभाव डालने वाले लोग, फिल्मी हस्तियाँ और सस्ते कपड़ों की बढ़ती मांग इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ावा दे रही है। रुझानों के तेजी से बदलने के कारण उपभोक्ताओं की पसंद भी लगातार बदलती रहती है, जिससे अत्यधिक उत्पादन और अनावश्यक खपत का एक अंतहीन चक्र चलता रहता है। इसका प्रभाव युवाओं और छात्रों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विद्यालयी कार्यक्रमों, विदाई समारोहों और विभिन्न सामाजिक आयोजनों में कई छात्र केवल इसलिए नए कपड़े खरीदने के लिए मजबूर महसूस करते हैं ताकि वे पुराने कपड़ों में न दिखें या दूसरों की आलोचना से बच सकें। दिखावे और सामाजिक स्वीकृति की यह मानसिकता फास्ट फ़ैशन को और अधिक बढ़ावा देती है। फास्ट फ़ैशन के दुष्परिणाम गंभीर और व्यापक हैं। कम गुणवत्ता वाले कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं और नए रुझान आने पर अक्सर फेंक दिए जाते हैं। इससे भारी मात्रा में वस्त्र कचरा उत्पन्न होता है। बढ़ती मांग और मुनाफे की होड़ में कई कंपनियाँ अनैतिक श्रम प्रथाओं का सहारा लेती हैं। दुनिया भर में अनेक फैशन ब्रांडों पर श्रमिकों के शोषण, कम वेतन और बाल श्रम के आरोप लग चुके हैं। कई कारखानों में कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर होते हैं।पर्यावरण पर इसका प्रभाव भी अत्यंत चिंताजनक है। बड़ी मात्रा में फेंके गए कपड़े कचरा भराव क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं, जिससे भूमि प्रदूषण बढ़ता है। कई वस्त्र कारखाने हानिकारक रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट जल स्रोतों में छोड़ते हैं, जिससे जल प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। इसके अतिरिक्त, कपड़ा उद्योग से होने वाला ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन को और तेज़ करता है। पॉलिएस्टर जैसी कृत्रिम सामग्री से बने अधिकांश फास्ट फ़ैशन उत्पाद वर्षों तक नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में हानिकारक सूक्ष्म प्लास्टिक छोड़ते रहते हैं।आज अत्यधिक उपभोग और उपभोक्तावाद सामान्य जीवनशैली का हिस्सा बन चुके हैं। लोग कपड़ों को एक मूल्यवान संसाधन के बजाय उपयोग करके फेंक देने वाली वस्तु के रूप में देखने लगे हैं। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि हम जो कपड़े पहनते हैं, वे कैसे बनाए जाते हैं और उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस दिशा में 3आर – कम उपयोग (रिड्यूस), पुनः उपयोग (रीयूज़) और पुनर्चक्रण (रीसायकल) के सिद्धांत को अपनाना बेहद आवश्यक है। अनावश्यक खरीदारी कम करके, कपड़ों का लंबे समय तक उपयोग करके तथा पुराने कपड़ों को दान या पुनर्चक्रित करके हम वस्त्र कचरे और पर्यावरणीय नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही, सस्ते और कम टिकाऊ कपड़ों के बजाय गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ वस्त्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को भी छात्रों के बीच सामाजिक मीडिया के रुझानों और अत्यधिक उपभोग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। जो लोग महंगे टिकाऊ कपड़े नहीं खरीद सकते, उनके लिए पुराने कपड़ों की पुनः खरीद एक जिम्मेदार और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प हो सकता है। इसके अतिरिक्त, स्वयं तैयार किया गया फैशन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसमें लोग पुराने कपड़ों को नया रूप देकर उनका पुनः उपयोग करते हैं। जिन लोगों के पास पहले से फास्ट फ़ैशन के कपड़े हैं, वे भी उन्हें अधिक समय तक पहनकर और फेंकने के बजाय दान करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। फास्ट फ़ैशन की बढ़ती चुनौती को देखते हुए समाज, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और सरकार को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। जागरूक उपभोक्ता व्यवहार, जिम्मेदार उत्पादन और प्रभावी नीतियों के माध्यम से ही हम एक अधिक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।क्षणिक रुझानों के पीछे भागने के बजाय हमें टिकाऊ जीवनशैली को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज का जिम्मेदार निर्णय ही आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर कल सुनिश्चित करेगा।

दिल्ली के मायापुरी में स्टील कटिंग फैक्ट्री में लगी आग, टला बड़ा हादसा

दिल्ली। मायापुरी में स्टील कटिंग एवं पैकिंग सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री में बृहस्पतिवार को भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग पहली और दूसरी मंजिल पर फैल गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, लगभग 500 वर्ग गज क्षेत्र में बनी यह इमारत बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दो मंजिलों वाली है, जिसमें कुछ हिस्से अस्थायी तथा कुछ स्थायी निर्माण के हैं। आग की तीव्रता के कारण भवन का कुछ हिस्सा भी ढह गया। मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंचीं। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। साथ ही आग किस वजह से लगी इसका पता अभी नहीं चल सका है।

ममता बनर्जी को चौथा झटकाः चार दिन में 4 इस्तीफे, कोयल मल्लिक ने भी छोड़ा दीदी का साथ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद तृणमूल कांग्रेस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पार्टी के भीतर शुरू हुई बगावत विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाईक और अभिनेत्री-सांसद कोयल मल्लिक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही पिछले चार दिनों में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले तृणमूल सांसदों की संख्या चार हो गई है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव भी उच्च सदन की सदस्यता छोड़ चुके हैं।

ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे TMC नेता

प्रकाश चिक बड़ाईक ने इस्तीफे के बाद कहा कि हालिया चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका सम्मान करते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। उन्होंने तृणमूल छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि भविष्य में वह मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही काम करेंगे। कभी अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले बड़ाईक को 2023 में तृणमूल ने राज्यसभा भेजा था और 2024 के लोकसभा चुनाव में अलीपुरद्वार से उम्मीदवार भी बनाया था। उन्होंने पार्टी के भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।

कोयल मल्लिक के इस्तीफे से राज्यसभा में बिगड़ा नंबर गेम

उधर, कोयल मल्लिक के इस्तीफे ने तृणमूल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। फरवरी में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था और अप्रैल में उन्होंने सांसद पद की शपथ ली थी। उस समय उन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बताया था, लेकिन अब पार्टी से दूरी बना ली है। लगातार इस्तीफों के कारण राज्यसभा में तृणमूल की संख्या 13 से घटकर नौ रह गई है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ और सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। लोकसभा में भी पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिख रही है, जहां बड़ी संख्या में सांसदों के असंतुष्ट खेमे के साथ जाने की चर्चा है। हालांकि इस उथल-पुथल के बीच अभिनेता-सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई है। उन्होंने कहा कि कठिन समय में वह न तो पार्टी छोड़ेंगे और न ही अपनी नेता का साथ। उनके अनुसार राजनीतिक मतभेदों के बावजूद नैतिक रूप से इस समय ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहना ही उचित है।

सायोनी घोष पर सस्पेंस बरकरार, कोलकाता लौटकर भी साधी चुप्पी

तृणमूल कांग्रेस में जारी राजनीतिक भूचाल के बीच सांसद और युवा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष सायोनी घोष को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। पार्टी के भीतर चल रही उठापटक के बीच उनका नाम उन नेताओं में शामिल किया जा रहा है, जिन्होंने बागी खेमे से नजदीकियां बढ़ा ली हैं। हालांकि सायोनी ने अब तक सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। सूत्रों के अनुसार बुधवार रात दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में सायोनी घोष, माला राय, यूसुफ पठान, प्रतिमा मंडल और मिताली बाग मौजूद थीं बाद में वहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे और सांसदों के साथ लंबी चर्चा की। बताया जा रहा है कि बैठक में बागी खेमे को मजबूत करने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर बातचीत हुई। इस घटनाक्रम के बाद तृणमूल के भीतर सायोनी की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक वर्ग खुलकर यह जानना चाहता है कि वह आखिर किस पक्ष में हैं। हाल के दिनों में पार्टी के विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में भी उनकी अनुपस्थिति और चुप्पी को लेकर असंतोष सामने आया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि वह तृणमूल के साथ हैं तो खुलकर सामने आएं और यदि बागी खेमे में शामिल हो चुकी हैं तो इसकी भी घोषणा करें। इसी बीच गुरुवार दोपहर सायनी घोष कोलकाता लौटीं। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे राजनीतिक रुख और कथित शिविर परिवर्तन को लेकर सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर पर टोपी, चेहरे पर मास्क और पूरी तरह चुप्पी साधे वह सीधे वाहन में बैठकर रवाना हो गईं।